संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को दफ्तरी भाषा का दर्जा दिया जाना

185. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार अभी तक हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की दफ्तरी भाषा का दर्जा नहीं दिला पायी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की दफ्तरी भाषा का दर्जा दिलाने के लिए क्या प्रयास किये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (ग) हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की एक आधिकारिक भाषा बनाने पर सरकार कई वर्षों से ध्यान देती रही है। संयुक्त राष्ट्र में नई भाषा लागू करने के लिए अत्यधिक वित्तीय व्यय के अतिरिक्त सदस्य राज्यों के बहुमत की भी आवश्यकता होती है। इस संबंध में हमारे परामर्श उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं। भारत सरकार अपने प्रतिनिधिमंडल के उन सदस्यों के लिए जो हिंदी में बोलना चाहते हैं, हिंदी अनुवाद, टंकण सुविधाएं मुहैया कराने के लिए न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में अस्थायी प्रबंध करती रही है। हिंदी में दिए जाने वाले भाषणों का मौके पर ही अनुवाद की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र तथा उसके विशिष्ट अभिकरणों में जब भी आवश्यकता होती है की जा सकती है।

Plea of Indian delegation at U.N. General Assembly Session regarding CTBT and NPT

186. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister and the Indian delegation to the U.N. General Assembly Session held in September this year made a plea for a just and fair world order in the context of CTBT and NPT and the need for Global-Disarmament, if so in what terms; and

(b) what was the response of the U.N. General Assembly and the different world leaders thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALEEM IQBAL SHERWAI): (a) Yes Sir. Prime Minister, in his address to the 52nd Session of the U.N. General Assembly, stated, inter alia, "The pretexts for clinging to nuclear arsenals, which were questionable at any time, have now vanished. Mere non-proliferation treaties, promoted as disarmament measures serve to entrench a nuclear monopoly...Global opinion wants a Nuclear Weapons Convention, as already outlined for the class of biological and chemical weapons, and will not rest till it is achieved. We appeal to nuclear weapon states to align their policies to what the world wants".

(b) The majority of leaders of the Non-Aligned countries are supportive of India's position. India's stand reflects the common position of the NAM countries on the issue of complete nuclear disarmament as a necessary step towards the establishment of a new, just and non-violent world order. However, consensus on this approach has not been possible due to the position of the nuclear-weapon-states.

सुरक्षा परिषद् में भारत की सदस्यता का समर्थन करने वाले देश

187. **श्री अजीत जोगी:**
श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में है; और

(ख) क्या अमरीका और चीन भी सुरक्षा परिषद् में भारत को शामिल किये जाने की बात का समर्थन कर रहे है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में से विभिन्न विचारधाराओं वाले अनेक देशों ने भारत की उम्मीदवारी का द्विपक्षीय रूप में अथवा संयुक्त राष्ट्र में समर्थन किया है।

(ख) अमरीका ने किसी देश का नाम लिये बिना यह स्वीकार किया है कि विकासशील देशों को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल किया जा सकता है। अमरीका ने यह भी कहा है कि वह स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का